[Shri P.S. Gadhavi]

It is pertinent to mention here that Jakhau is strategically located and has national security importance. The Government of India has accorded administrative approval on this project under 100 per cent CSS, as a special case.

I, therefore, urge upon the Central Government to sanction and release the difference amount of Rs. 23.41 crore incurred by the State Government on the project, as immediately as possible.

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, मुझे इस सीट से बोलने की इजाजत दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको इस सीट से बोलने की इजाजत दी जाती है।

डॉ. करण सिंह यादव: महोदय, इन दिनों में राजस्थान में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र अलवर में सरसों और गेहूं की बुआई का सीजन शुरू है। लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां के किसानों को डीएपी खाद प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रहा है और इसकी बहुत कमी है। यहां से राजस्थान के लिए कोटा एलॉटमेंट कम है, कुछ ब्लैक मार्किट में चला जाता है जिसके कारण अलवर के किसान हरियाणा से कालाबाजारी से खरीदकर लाते हैं। इसकी गुणवत्ता बहुत कम है और किसान ठगा जा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में विशेष तौर से अलवर जिले में डीएपी की मात्रा का कोटा बढ़ाया जाए और उचित व्यवस्था की जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, मारवाड़ी हिन्दुस्तान की पश्चिमी बोली में राजस्थानी समूह की सबसे बड़ी बोली है। प्राय: मारवाड़ी को राजस्थानी के पर्याय के रूप में जाना जाता है लेकिन ये बोली मुख्यत: राजस्थान के मध्य एवं पश्चिमी भाग के बीकानेर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में बोली जाती है। इस क्षेत्र को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ी समुदाय एक ऐसा व्यावसायिक समुदाय है जो दुनिया भर में फैला हुआ है और इनका अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव है। अत: ये घर परिवार सामाजिक कार्यों में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती है इसके बोलने वालों की संख्या लगभग एक करोड़ है। हिन्दी की तरह मारवाड़ी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इसका व्याकरण भी हिन्दी जैसा ही है। इसके 50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक शब्द हिन्दी जैसे ही हैं। मारवाड़ी का शिक्षा के माध्यम या सरकारी कामकाज में उपयोग नहीं होता है इसका कारोबार में उपयोग होता है। राजस्थानी समूह की अन्य बोलियों में हाडोती, मेवाढ़ी, ढूढारी, मेवाती, शेखावटी और बागड़ी आदि शामिल हैं। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि संविधान की आठवीं सूची में इस भाषा को शामिल किया जाए जिससे इसकी मान्यता और उपयोग बढ़ सके और राजस्थानी भाषा को भी मान्यता मिल सके।

डा. करण सिंह यादव: आप राजस्थान के टुकड़े क्यों कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

*...(Interruptions)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आपने राजस्थान की जो खाद की समस्या बताई है मैं तो आपके साथ एसोसिएट कर रहा हूं। लेकिन राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है, अगर मारवाड़ी मिल जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। *...(व्यवधान)*

MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing would go on record now.

*(Interruptions)** ...

SHRI P.C. THOMAS (Muvattupuzha): The waiver and the relief scheme to the farmers is a very good scheme which is going to help many farmers. But when the scheme was to be implemented, the Government framed guidelines and according to those guidelines many of the declared benefits which were to accrue to the farmers have been curtailed. I can quote one example. In the Budget declaration in the Lok Sabha it was mentioned that all loans before 31.03.07 will be waived in case of all those eligible ones. But when it came to implementation, clause 4 of the guidelines stipulated that all long term loans before 01.03.97 will be out of the scheme. That is totally against what had been declared in the Lok Sabha.

There is another one and that is for short-term loans it was said that all the loans would be waived. But when it came to the guidelines, clause 3 of the guidelines states that in case of short-term loans a limit is fixed and that is Rs. 1,00,000/-. Any loan above Rs. 1,00,000/- would

*Not recorded.